

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 62/2024

अपीलार्थी-

1. कोजराज सिंह पुत्र धारा
2. अशोकसिंह पुत्र धारा
3. निम्बसिंह पुत्र धारा
4. कमलसिंह पुत्र धारा जाति
दारोगा निवासी निम्बासर
तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

1. तहसीलदार शिव
2. गोमा पुत्र जोगा जाट निवासी
निम्बासर, तहसील शिव जिला
बाड़मेर
3. अमराराम पुत्र जोगाराम जाति
जाट निवासी निम्बासर,
तहसील शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.12.2024 जो प्रकरण सं.
67/2024 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

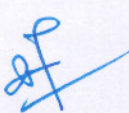
1. श्री सुरेश सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री किशनाराम चौधरी, रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से
उपस्थित।
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 09.12.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं.
67/2024 सरकार बनाम गोमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.12.
2024 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का निम्बासर
द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
मौजा निम्बासर के खसरा नम्बर 36, 37, 38 रकबा 28.4979, 28.4951, 28.
3280 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन धोरा, बारानी सोयम में गैर सायल




जिला कलक्टर
बाड़मेर

गोमाराम, अमराराम द्वारा राजकीय भूमि पर झौपा, कच्ची डिग्गी, तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं हुए इस पर तहसीलदार शिव द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 10.12.2024 के द्वारा 2773/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने दिनांक 23.12.2024 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये समन तलब किया।
4. अपीलांत के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा निम्बासर के खेत खसरा नम्बर 36, 37, 38 का आया हुआ है उक्त भूमि में बस्ता पुत्र गोखला द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/1971 पेश किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 13.07.1971 को किया गया एवं बस्ता को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया गया एवं डिक्री की पालना में राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज बदल दिये गये एवं बस्ता का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त भूमि के मूल खातेदार के विरुद्ध सिलिंग रिऑपन का प्रकरण चला जिसमें सगतसिंह वगैरा के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि मानी गई तो संगतसिंह वगैरा ने विकल्प पेश करते समय बस्ता के खातेदारी की भूमि के सदर्थ में विकल्प पेश किया जिस विकल्प को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि खालसा दर्ज कर दी गई तब जिला कलक्टर के समक्ष बस्ता के वारिसान द्वारा उजरदारी पेश की गई जो उजरदारी खारिज की गई। तत्पश्चात बस्ता के वारिसान ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3311/1995 पेश की जो दिनांक 29.07.




जिला कलक्टर
बाड़मेर

2002 को स्वीकार की गई एवं यह आदेश पारित किया गया कि भारक्त भूमि ही विकल्प में स्वीकार कर अधिग्रहण की जावे एवं विवादग्रस्त भूमि को भार मुक्त नहीं माना गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 29.07.2002 के विरुद्ध खण्डपीठ में विशेष अपील संख्या 551/2002 पेश की गई जो दिनांक 13.05.2016 में खारिज की गई। इस प्रकार एकलपीठ का निर्णय दिनांक 29.07.2002 यथावत रहा एवं एकलपीठ के निर्णय की पालना में भारमुक्त भूमि अधिग्रहण करने एवं भारयुक्त को मुक्त करने हेतु कार्यवाही विचारधीन है। जिसमें तहसीलदार एवं पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में पेश की गई है। एकलपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने का पुनः भूमि डिक्रीदार अर्थात् बस्ता के वारिसान के नाम दर्ज की जानी है। इस भूमि पर बस्ता के वारिसान जो अपीलार्थीगण है, निरंतर काबिज है एवं कब्जा काशत करते आ रहे हैं, वर्तमान में अपीलार्थीगण की काशत खड़ी है। पटवार हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण इस भूमि पर अपीलार्थीगण की ओर से काम कर रहे मजदूरों के विरुद्ध दर्ज किया एवं उनके नाम से नोटिस दिनांक 06.12.2024 को जारी करने का आदेश दिये एवं आगामी पेशी दिनांक 10.12.2024 मुकर्रर की गई। उक्त पेशी का नोटिस मिलने पश्चात दोनों मजदूर वकील के साथ तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना सुनवाई किये प्रकरण में बेदखली एवं मौके पर खड़ी फसल को जब्त कर निलाम करने का आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध है। जो निरस्त योग्य हैं।

रिस्पो संख्या 02 एवं 03 के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरो पर मजदूरी का कार्य किया जा रहा था तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उक्त 91 प्रकरण दर्ज कर बिना सुनवाई बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है।


6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्त ने इस अपील के द्वारा ग्राम निम्बासर के गोमु0 राजकीय भूमि पर झौपा, कच्ची डिग्गी,



तारबंदी एवं काश्त किया जाना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन धोरा दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो संख्या 02 एवं 03 को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 10.12.2024 हेतु तलब किया गया, सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से रेस्पो. संख्या 02 एवं 03 को राजकीय भूमि से बेदखल कर कब्जा राज किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 उनके कृषि मजदूर हैं जबकि मौके पर कब्जा-काश्त उनकी ओर से की गई हैं तथा अपीलांट का कब्जा किसी भी रूप में अनाधिकृत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पाया जाता है कि जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 का राजकीय मुतनाजा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होने की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किये गये तब इसकी सूचना रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स की दी जानी चाहिए थी। यद्यपि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 उनके कृषि मजदूर होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसके उपरांत भी अपीलांट जिस खसरा नम्बर 36 व 38 पर अपना हित अधिकार होना प्रकट किया है, के अलावा रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 का खसरा संख्या 37 राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण होना पाया गया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर अवैध कब्जाधारी रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के विरुद्ध जो अपीलाधीन कार्यवाही अमल में लाई जाकर उन्हें अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 के विरुद्ध पारित किया गया





जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश 10.12.2024 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अपीलांत यदि मुतनाजा भूमि पर न्यायिक निर्णयों के आधार पर अपना हित अधिकार होना मानता हैं तो उसके लिये सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर